विचार बिन्दु

भूख प्यास से जितने लोगों की मृत्यु होती है उससे कहीं अधिक लोगों की मृत्यु ज़्यादा खाने और ज़्यादा पीने से होती है। –कहावत

अमीरों के खर्च बढ़े, मगर निम्न मध्यम वर्ग पिसा

खबर है कि भारत के 10 करोड़ सबसे अमीर लोग शादियों, गहनों और सबसे महंगी श्रेणी के अपार्टमेंट पर खूब खर्च कर रहे हैं, वहीं 40 करोड़ से अधिक निम्न मध्यमवर्गीय देशवासी रसोई तथा दैनंदिनी सामान की खरीद में कटौती कर रहे हैं। पिछली तिमाही में जवाहरात बेचने वाली कंपनियों की आमदनी में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। इसी प्रकार एसयूवी (स्पोर्ट यूटिलिटी वाहन) कार बनाने वाली कंपनियों ने अपनी बिक्री में दिसंबर में 16 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित की। लेकिन आम आदमी की जरूरतों को पूरा करने वाली उपभोक्ता कंपनियों के नवीनतम व्यवसाय अपडेट संकेत देते हैं कि वे अपने सकल मार्जिन में संकुचन और परिचालन लाभ में मामूली से सपाट वृद्धि ही पा रही हैं। बाजार अनुसंधान करने वाले विशेषज्ञ कहते हैं कि यह एक 'बाइ पोलारिटी' है, जहां बाजार का प्रीमियम सिरा तो आगे बढ़ रहा है, जबकि निम्न मध्य वर्ग को पूर्ति करने वाला सिरा सिकुड़ रहा है। इन विशेषज्ञों को मध्यम आकार के शहरों में मंदी दिख रही है। वे बताते हैं कि मध्यम आकार के सामान की बिक्री अच्छी नहीं है। इसके अलावा मध्यम श्रेणी की उपभोक्ता वस्तुओं में भी वृद्धि नहीं हो रही है। उपभोग भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 60 प्रतिशत माना जाता है और उसमें सामने आ रहे अलग–अलग रुझानों पर अर्थशास्त्रियों तथा समाजशास्त्रियों की नज़र है। उनको लग रहा है कि धीमी वेतन वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई के कारण कम आय वाले लोगों पर वित्तीय दबाव पड़ा है, जिससे वे खरीदारी छोड़ रहे हैं या कम कर रहे हैं, जबकि अमीर जमकर खर्च कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने अपने बजट में खपत को बढ़ाने को ध्यान में रख कर प्रावधान किये गये हैं, मगर इनमें अधिकतर उच्च मध्यम श्रेणी के लोगों के जेब में अधिक पैसा डालते हैं। भारत की खपत की कहानी हमेशा से ही आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक रही है। बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था के पैरोकारों को बढ़ते मध्यम वर्ग, बढ़ते शहरीकरण और विभिन्न श्रेणियों में खर्च करने की बढ़ती इच्छा के कारण खपत–आधारित विकास की संभावना बहुत अधिक नज़र आती है। उन्हें यह संभावना उपभोक्ता फर्मों के सार्वजनिक और निजी बाजार मूल्यांकन में भी नज़र आती है। हालांकि, खर्च लायक सीमित आय, मुद्रास्फीति, तनावपूर्ण बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्र सहित कई चुनौतियां उन्हें उपभोक्ता खर्च को बाधित करती भी दिखती हैं जो उनके अनुसार खपत को प्रभावित करती हैं। इसीलिए समाज के व्यापक वर्गों–निम्न मध्यम वर्ग को सेवा देने वाली कंपनियां शायद सबसे अधिक प्रभावित हो रही हैं।

बताते हैं भारत का उपभोक्ता बाजार 2030 तक 46 प्रतिशत बढ़ने की राह पर है, जिससे यह वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। बढ़ती आय, युवा कार्यबल और तेजी से शहरीकरण से देश भर में खपत में वृद्धि होने की उम्मीद है। अनुमानों के अनुसार, भारत में उपभोक्ता खर्च 2030 तक 4.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ जाएगा, जो 2024 में 2.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह वृद्धि मुख्य रूप से भारत की मध्यम और उच्च–मध्यम आय वाली आबादी के विस्तार से ही प्रेरित है, जिससे उनकी क्रय शक्ति और विवेकाधीन खर्च में वृद्धि हो रही है। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो 2018 में 23 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 42 प्रतिशत हो गई है। इससे उच्च माध्यम वर्ग बढ़ रहा है। दोहरी आय वाले परिवारों को यह वृद्धि उनकी नई जीवनशैली और प्रीमियम उत्पादों पर अधिक खर्च की ओर ले जा रही है। इसे भारत की उपभोक्ता अर्थव्यवस्था का मजबूत होना माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त, देश में खपत में दो बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ये बदलाव है उपभोक्ताओं का बिना ब्रांड वाले से ब्रांडेड उत्पादों की ओर झुकाव तथा असंगठित खुदरा व्यापार पर संगठित खुदरा व्यापार का हावी होना। इन बदलावों से आने वाले वर्षों में 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त उपभोक्ता खर्च होने की बाज़ार के विश्लेषकों को यकीन है। इसके अतिरिक्त, आसान ऋण उपलब्धता उपभोक्ताओं के लिए विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करना आसान बना रही है। यही कारण है कि प्रीमियमाइजेशन अर्थात उच्च–स्तरीय और ब्रांडेड उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लंबे समय बाद रेपोरेट को घटा कर ब्याज दरों को कम करना भी खपत को बढ़ावा देने वाला कदम ही है। मगर इस सारे माहौल में निम्न और निम्न मध्यम वर्ग की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। नीति निर्माता यह मान बैठे हैं कि उच्च और उच्च माध्यम वर्ग जब खर्च करेगा तो उससे बाज़ार गुलज़ार होगा जिससे निचले लोगों के हाथों को काम मिलेगा। किन्तु निम्न वर्ग के लिये गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य पर जरूरी निवेश नहीं किया जा रहा है। सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य को अधिकतर निजी क्षेत्र के भरोसे छोड़ दिया है। अनेक योजनाओं के नाम पर गरीबों को मुफ़्त राशन तथा मामूली वित्तीय सहायता देकर सरकार मान चली है कि उसने गरीबों की मदद कर दी है। इससे अर्थ व्यवस्था तो ऊंची उठ रही है मगर गरीब के विकास के गति उससे मेल नहीं खा रही है। रिजर्व बैंक ने अपनी नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा है कि लगभग 50,000 रुपये का व्यक्तिगत ऋण लेने वाले 11 प्रतिशत उधारकर्ता समय पर पुनर्भुगतान करने में विफल रहे और 60 प्रतिशत से अधिक ने 2024 की शुरुआत से तीन से अधिक ऋण लिए थे। आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण करने वाले कहते हैं कि यह कंपनियों के लिए भी यह चिंता का विषय है क्योंकि मध्यम खंड जो मात्रा और मूल्य दोनों विकास को चलाता है, वह खर्च नहीं कर रहा है। वे कहते हैं कि कि प्रीमियम खंड, जो जनसंख्या का 5 से 10 प्रतिशत है, इन कंपनियों को वह विकास नहीं दे सकता है जिसकी उन्हें जरूरत हैं।

> **भले ही भारत का उपभोक्ता बाजार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने की उम्मीद रखता है मगर आर्थिक असमानता स्वाभाविक ही अशान्ति पैदा करती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि आर्थिक दबाव और खराब हो सकते हैं। कोरोना महामारी के बाद से देश में खपत में यह असमानता अधिक उजागर हो रही है। सीधे शब्दों में कहें तो जहा एक तरफ अमीर खूब खर्च कर रहे हैं वहीं गरीब को पेट पर पट्टी बांधने को मजबूर होना पड़ रहा है।**

पिछले कुछ वर्षों में भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों पर उपभोक्ता व्यय में गिरावट देखी गई है। अनाज जैसी बुनियादी वस्तुओं में भारी गिरावट देखी गई है। ग्रामीण भारत में, एमपीसीई के प्रतिशत के रूप में अनाज पर व्यय 1999–2000 के 22.16 प्रतिशत से घटकर 2022–23 के दौरान 4.89 प्रतिशत रह गया। इसी तरह, शहरी भारत में, यह 1999–2000 के एमपीसीई के 12.35 प्रतिशत से घटकर 2022–23 के दौरान 3.6 प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत, ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में पिछले कुछ दशकों में गैर–खाद्य व्यय में लगातार वृद्धि हुई है। ग्रामीण भारत में, उपभोक्ता सेवाओं और टिकाऊ वस्तुओं जैसी गैर–खाद्य वस्तुओं की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उपभोक्ता सेवाओं पर व्यय 1999–2000 के 2.98 प्रतिशत से बढ़कर 2022–23 के दौरान 5.08 प्रतिशत हो गया, जबकि टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च 1999–2000 के 2.62 प्रतिशत से तीन गुना बढ़कर 2022–23 के दौरान 6.89 प्रतिशत हो गया। यह उछाल ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च के पैटर्न में आ रहे बदलाव को उजागर करता है, जहां उपभोक्ता गैर–ज़रूरी वस्तुओं पर अधिक खर्च कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, सांख्यिकी मंत्रालय के 2022–23 के नवीनतम सर्वेक्षण में मासिक खपत में भोजन की हिस्सेदारी घटकर 46.4 प्रतिशत हो गई, जो 2011–12 में 53 प्रतिशत थी। इसके विपरीत, गैर–खाद्य खपत 2011–12 के 47 प्रतिशत से बढ़कर 2022–23 के दौरान 53.6 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में खाद्य व्यय का हिस्सा 42.6 प्रतिशत से घटकर 39.2 प्रतिशत हो गया, जबकि गैर–खाद्य व्यय का हिस्सा 57.4 प्रतिशत से बढ़कर 60.8 प्रतिशत हो गया।

भारतीय उपभोक्ता बास्केट को देखते हुए देश की सामाजिक–आर्थिक विविधता को ध्यान में रखना जरूरी है। भारत के लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में सबसे नीचे के वर्ग के लोगों को शामिल किये बिना देश की अर्थव्यवस्था का ऊंचे चढ़ना कोई अर्थ नहीं रखता। भले ही भारत का उपभोक्ता बाजार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने की उम्मीद रखता है मगर यह बाज़ार ऊपर के तबके का हो कर न रह जाए यह सभी की चिंता होनी चाहिए। आर्थिक असमानता स्वाभाविक ही अशान्ति पैदा करती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि आर्थिक दबाव और खराब हो सकते हैं। कोरोना महामारी के बाद से देश में खपत में यह असमानता अधिक उजागर हो रही है। सीधे शब्दों में कहें तो जहा एक तरफ अमीर खूब खर्च कर रहे हैं वहीं गरीब को पेट पर पट्टी बांधने को मजबूर होना पड़ रहा है। खबरों के अनुसार विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में 2025–26 में विकास दर 6.2 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना जताई है, जिसमें भारत की स्थिर विकास दर प्रमुख भूमिका निभाएगी। विश्व बैंक ने अपने नवीनतम विकास दर अनुमानों में कहाहै कि "भारत में विकास दर अगले दो वित्तीय वर्षों के लिए 6.7 प्रतिशत प्रति वर्ष स्थिर रहने का अनुमान है, जो अप्रैल 2025 से शुरू हो रहा हैं।" विश्व बैंक को सेवा क्षेत्र में लगातार विस्तार की संभावना नज़र आती है। उसे विनिर्माण गतिविधियां भी मजबूत होने का भरोसा है। ये सारी परिस्थितियां गरीब को परेशान करने वाली है। यदि नीति निर्माता केवल अर्थव्यवस्था के ग्राफ को देख कर ही संतुष्ट होकर अपनी पीठ ठोंकते रहेगे तो यह आर्थिक असमानता देश में सामाजिक बेचैनी का सबब भी बन सकती है। नए केन्द्रीय बजट में सरकार की पहलें उच्च और उच्च मध्यम वर्ग को तो लुभाएगी लेकिन नीचे के तबके की आस कितना पूरा कर पाएगी इसे देखना होगा।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

उच्च शिक्षा में समान पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के विरुद्ध है

अशोक कुमार

शिक्षा एक मौलिक मानव अधिकार है, आर्थिक और सामाजिक प्रगति का एक प्रमुख चालक है। शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 पेश की, जो देश में शिक्षा के विकास के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। NEP 2020 का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, समग्र और लचीला बनाकर बदलना है। NEP 2020 का उद्देश्य अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देकर, नए बहु–विषयक संस्थानों की स्थापना करके और उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) को बढ़ाकर देश में उच्च शिक्षा को बदलना है। रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए, संस्थानों और संकाय के पास उच्च शिक्षा योग्यता के व्यापक ढांचे के भीतर पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन के मामलों में नवाचार करने की स्वायत्तता होगी जो संस्थानों और कार्यक्रमों में और ओडीएल, ऑनलाइन और पारंपरिक ;में स्थिरता सुनिश्चित करती है।

तदनुसार, सभी छात्रों के लिए एक उत्तेजक और आकर्षक सीखने का अनुभव सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों और प्रेरित संकाय द्वारा पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र तैयार किया जाएगा, और प्रत्येक कार्यक्रम के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाएगा। सभी मूल्यांकन प्रणालियां भी HEI (Higher Education Institutes) द्वारा तय की जाएंगी, जिनमें वे भी शामिल हैं जो अंतिम प्रमाणन की ओर ले जाती हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) को नवाचार और लचीलेपन को बढ़ाने के लिए संशोधित किया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थान एक मानदंड–आधारित ग्रेडिंग प्रणाली की ओर बढ़ेंगे जो प्रत्येक कार्यक्रम के लिए सीखने के लक्ष्यों के आधार पर छात्र की उपलब्धि का आकलन करती है, जिससे प्रणाली को निष्पक्ष और परिणामों को अधिक तुलनीय बनाया जा सके। उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उच्च–दांव वाली परीक्षाओं से अधिक सतत और व्यापक मूल्यांकन की ओर भी जाना चाहिए।

उच्च शिक्षा में स्वायत्तता को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा शैक्षणिक मानकों और उत्कृष्टता में सुधार के संबंध में शैक्षणिक विकास की दिशा में अधिक लचीलापन देने के लिए विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों को दी गई एक कार्यात्मक स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक स्वायत्त कॉलेज को अपने लिए और स्वशासन के लिए एक आदर्श बनने की स्वतंत्रता दी जाती है। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों की स्वायत्तता, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों को मान्यता के साथ बेहतर ढंग से काम करने के लिए अधिक शैक्षिणक और परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करके संबद्ध विश्वविद्यालय की ओर से डिग्री प्रदान करने में सक्षम बनाती है। स्वायत्त कॉलेजों के लिए यूजीसी दिशानिर्देश (2018) स्वायत्त कॉलेजों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए संकेत देते हैं कि स्नातक शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का एकमात्र सुरक्षित और बेहतर तरीका अधिकांश कॉलेजों को संबद्ध प्रणाली से अलग करना है। इसके अलावा, यह कहा गया है कि शैक्षणिक और संचालन स्वतंत्रता वाले कॉलेज बेहतर कर रहे हैं और उनकी विश्वसनीयता अधिक है और ऐसे कॉलेजों को वित्तीय सहायता स्वायत्तता की अवधारणा को बढ़ावा देती है।

सामान्य उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उच्च शिक्षा में एक सामान्य पाठ्यक्रम का विचार कुछ राज्यों में दिया गया है। यह विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के खिलाफ है। शिक्षा की गुणवत्ता की अपर्याप्तता के मुद्दे पर गहन मूल्यांकन की आवश्यकता है। यद्यपि पाठ्यक्रम शिक्षण–सीखने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए रूपरेखा तैयार करता है, गुणवत्ता मुख्य रूप से अधिक सीखने के लिए शिक्षण–सीखने की प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता द्वारा तय की जाती है। संस्थागत नेतृत्व, शिक्षकों और कर्मचारियों की दृष्टि, क्षमता और प्रतिबद्धता उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समान पाठ्यक्रम रखने की लफ्फाजी अंततः कुछ उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा विशिष्टता प्राप्त करने की संभावना को कम कर देगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल उद्देश्य सामान्य सिलेबस को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। खंड (11.6)। ई 2020 नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बड़े बहु–विषयक विश्वविद्यालय और कॉलेज उच्च–गुणवत्ता वाली समग्र और बहु–विषयक शिक्षा की ओर बढ़ने में मदद करेंगे। किसी विषय या विषयों में कठोर विशेषज्ञता के अलावा पाठ्यक्रम में लचीलापन और नए और आकर्षक पाठ्यक्रम विकल्प छात्रों को प्रदान किए जाएंगे। पाठ्यक्रम की स्थापना में संकाय और संस्थागत स्वायत्तता में वृद्धि से इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। अध्यापन में संचार, चर्चा, बहस, अनुसंधान और क्रॉस–डिसिप्लिनरी और अंत:विषय सोच के अवसरों पर अधिक जोर दिया जाएगा। आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति खंड (12.2) पढ़ता है ;रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए, संस्थानों और संकाय के पास पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन के मामलों में नवाचार करने की स्वायत्तता होगी ...तदनुसार, पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र संस्थानों द्वारा डिजाइन किए जाएंगे और प्रेरित संकाय सभी छात्रों के लिए सीखने का अनुभव सुनिश्चित करना और उत्तेजक और आकर्षक बनाना।

सामान्य रूप से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उच्च शिक्षा में एक सामान्य पाठ्यक्रम का विचार कुछ राज्यों में दिया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता की अपर्याप्तता के मुद्दे पर गहन मूल्यांकन की आवश्यकता है। यद्यपि पाठ्यक्रम, शिक्षण–सीखने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए रूपरेखा तैयार करता है, गुणवत्ता मुख्य रूप से शिक्षण–सीखने की प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता द्वारा तय की जाती है। संस्थागत नेतृत्व, शिक्षकों और कर्मचारियों की दृष्टि, क्षमता और प्रतिबद्धता उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समान पाठ्यक्रम रखने की लफ्फाजी अंततः कुछ उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा विशिष्टता प्राप्त करने की संभावना को कम कर देगी।

विश्वविद्यालयों में समान पाठ्यक्रम होने के बारे में क्या होना चाहिए यह एक व्यापक विषय है ! इस विषय पर विचारों में भिन्नता हो सकती है। अतः इस महत्वपूर्ण विषय पर विचारधारा और प्राथमिकताएं पर गंभीरता से विमर्श होना चाहिए । समान पाठ्यक्रम के पक्षधरों का कहना है कि यह मानकीकरण और विश्वस्तरीकरण को प्रोत्साहित करेगा और छात्रों को एक ही सेट के ज्ञान और कौशलों के साथ परिचित कराएगा। इससे सभी छात्रों को समानता की भावना और सामान्य ज्ञान की एक साझी आधारभूत ज्ञान की दृष्टि मिल सकती है। यह उन क्षेत्रों के छात्रों के लिए भी लाभदायक होगा जो बच्चे पर्याप्त संसाधनों के अभाव में हैं और जिनके पास अच्छी शिक्षा के लिए पहुंच नहीं है। समान पाठ्यक्रम का होना विश्वविद्यालयों के बीच सामंजस्य बनाता है और छात्रों को एक समान स्तर पर पढ़ाई करने का मौका देता है। इससे छात्रों की योग्यता और ज्ञान की दृष्टि से एक समान आकलन होता है। एक समान पाठ्यक्रम उन छात्रों के तनाव को कम करने में मदद करेगा जिनके माता–पिता के पास स्थानांतरणीय नौकरियां हैं कि छात्र जहां भी जाते हैं उन्हीं पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं, इससे आगे किसी भी खरीद की लागत को कम करने में मदद मिलेगी। इससे छात्रों के दिमाग पर बोझ भी कम होता क्योंकि वे हर जगह एक ही पाठ्यक्रम का पालन कर सकते थे, एक समान सेवा नए पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के साथ समायोजित करने में मदद करती है, जो कि नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम एक बहुत ही कीमती वर्ष का नुकसान हो सकता है।

विपक्षी तत्त्वों का कहना है कि समान पाठ्यक्रम नवाचार और रचनात्मकता को दबा सकता है और एकल अधिकारियों को अपनी विशेषताओं और विषयों पर विशेष प्रोग्राम विकसित करने की क्षमता सीमित कर सकता है। समान पाठ्यक्रम से छात्रों के अंदर नये और आविष्कारी विचार पैदा नहीं होते हैं और छात्रों के साथ उनकी आस्था और संस्कृति के अनुरूप पाठ्यक्रम को न बताया जाना सही नहीं होता है। इसके अलावा, देश में विविधता के कारण अलग–अलग राज्यों में भी अलग–अलग संस्थान होते हैं जो अपने–अपने विशिष्ट रूप से छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं।

उच्च शिक्षा विशेष ज्ञान का प्रसार करने के बारे में है। मान्यता के लिए प्रत्येक संस्थान को अपना विशिष्ट डोमेन विकसित करना चाहिए। संस्थानों में एक सामान्य पाठ्यक्रम ज्ञान के ऐसे विशेष केंद्रों की भावना के खिलाफ है। दूसरे, संस्थानों में एक सामान्य पाठ्यक्रम विशेष रूप से भारत जैसे देश में स्थानीय और क्षेत्रीय चिंताओं को मिटाने की संभावना है। विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान और मानविकी में उस क्षेत्र के छात्रों के दिमाग को पूरा करने के लिए ज्ञान प्रसार में क्षेत्रीय विविधताओं पर जोर होना चाहिए। सामान्य पाठ्यक्रम ऐसा करने में विफल रहता है। एक सामान्य पाठ्यक्रम न केवल क्षेत्रीय रूप से बल्कि समुदाय, धर्म, जाति, लिंग आदि के संदर्भ में विविध हितधारकों से इनपुट लेने में विफल रहता है। उदाहरण के लिए यूपी के एक विश्वविद्यालय से भारतीय साहित्य का पेपर महाराष्ट्र के एक विश्वविद्यालय से अलग होगा। या तमिलनाडु का इतिहास का पाठ्यक्रम असम के किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से भिन्न होगा। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सभी छात्रों को पढ़ाने के लिए एक ही पाठ्यक्रम अलग–अलग होना चाहिए !

समान पाठ्यक्रम से छात्रों के अंदर नये और आविष्कारी विचार पैदा नहीं होते हैं और छात्रों के साथ उनकी आस्था और संस्कृति के अनुरूप पाठ्यक्रम को न बताया जाना सही नहीं होता है। इसके अलावा, देश में विविधता के कारण अलग–अलग राज्यों में भी अलग–अलग संस्थान होते हैं जो अपने–अपने विशिष्ट रूप से छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं। जब तक पाठ्यक्रमों में विविधता नहीं होगी तब तक नये विषयों का सृजन नहीं होगा । जब तक सभी विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में समान बुनियादी ढाँचे– शिक्षक, प्रयोगशाला, विषय से सम्बन्धित उपकरण, पुस्तकालय आदि उपलब्ध नहीं होंगे तब तक समान पाठ्यक्रम लागू करना घातक भी हो सकता है । महाविद्यालयों में यह होना सम्भव नहीं लगता । मुख्यता उच्च शिक्षा में एक सामान्य पाठ्यक्रम का विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के विरुद्ध है।

–अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय, विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

300 से अधिक प्रिंसिपल पदोन्नत होकर बनेंगे डीईओ

बोर्ड परीक्षा से पहले पदस्थापन की उम्मीद, इनमें से 50 रिटायर भी हो चुके हैं

बीकानेर, (निसं)। राज्य सरकार ने 10वीं–12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से पहले जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) के रिक्त पदों को भरने की तैयारी कर ली है। डीईओ पदों की डीपीसी होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में प्रो. अय्यूब खान की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 की नियमित के साथ 2022–23 में डेफर रखे गए प्रकरणों पर मंथन होगा। इस बकाया डीपीसी में लगभग 300 प्रिंसिपल के डीईओ पदों पर चयनित होने की संभावना है।

> ■ **राज्य में जिला शिक्षा अधिकारियों के 250 से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं**

जानकारी के अनुसार राज्य में जिला शिक्षा अधिकारियों के 250 से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं। उधर, 6 मार्च से 10वीं–12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है।

बीकानेर में वर्तमान में डीईओ माध्यमिक एवं प्रारंभिक दोनों पद रिक्त चल रहे हैं। चयन वर्ष 2022–23 की डीपीसी के बाद रामगोपाल मीणा बीकानेर डीईओ एलीमेंट्री के पद पर लगाया गया था, लेकिन मीणा की ओर से पदोन्नति का त्याग करने के कारण यह पद रिक्त हैं।

वहीं डीईओ माध्यमिक का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे एडीपीसी समग्र शिक्षा गजानन सेवग भी पिछले महीने सेवानिवृत्त हो चुके हैं। डीईओ पदों पर पदोन्नति के बाद राज्य में डीईओ के लगभग 250 पद भरने की संभावना है। दरअसल, डीपीसी में 300 प्रिंसिपल के चयनित होने की उम्मीद है, लेकिन लगभग 50–60 प्रिंसिपल वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ऐसे में कुल मिलाकर 250 पद ही भरे जा सकेंगे।

पदोन्नत प्रिंसिपल की काउंसलिंग स्थगित

बीकानेर, (निसं)। प्रदेशभर के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को फिलहाल प्रिंसिपल नहीं मिल पाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश को वापस लेते हुए इस प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया है। अब इसी महीने में नई तारीख जारी हो सकती है।

> ■ **प्रदेशभर के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को फिलहाल नहीं मिल पाएंगे प्रिंसिपल**

जानकारी के अनुसार राज्यभर में प्रिंसिपल काउंसलिंग के लिए तैयारी चल रही थी। उम्मीद की जा रही थी कि नई स्कूलों में बोर्ड एग्जाम से पहले ही प्रिंसिपल पहुंच जाएंगे। शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन काउंसिलिंग के लिए कार्यक्रम भी जारी कर दिया था। एक दिन पहले ही सिनियोरिटी की स्थायी लिस्ट भी जारी कर दी, लेकिन अचानक इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया। निदेशालय से जारी आदेश में कहा गया है कि अपरिहार्य कारणों से ऑनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम स्थगित किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ दिन बाद ही नया कार्यक्रम जारी होगा। शिक्षा निदेशालय ने काउंसिलिंग के लिए पूरी तैयारी कर ली थी लेकिन जयपुर से ही काउंसिलिंग स्थगित करने के आदेश आ गए, जिसके बाद इसे टाल दिया गया। दरअसल, राज्य के चार हजार से ज्यादा स्कूलों को प्रिंसिपल इस काउंसिलिंग के बाद मिलने वाले हैं। काउंसिलिंग के लिए स्कूलों को ऑनलाइन ओपन करना होता है। इसके बाद ही प्रमोटेड टीचर्स उसने में विकल्प भर सकते हैं। माना जा रहा है कि स्कूल ओपन करने के मामले में ही सहमति नहीं बनने के कारण इसे टाल दिया गया।

जेईई–मेन जनवरी सेशन का रिजल्ट जारी

राजस्थान से सर्वाधिक पांच स्टूडेंट्स को 100 एनटीए स्कोर मिला

कोटा, (निसं)। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई–मेन जनवरी सेशन का परिणाम जारी कर दिया है। कुल 10 शिफ्टों में हुई परीक्षा में 14 स्टूडेंट्स ने 100 एनटीए स्कोर प्राप्त किया है, जिसमें राजस्थान के सर्वाधिक 5 विद्यार्थी, दिल्ली के 2, उत्तर प्रदेश के 2, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक एवं तेलंगाना के 1–1 विद्यार्थी शामिल हैं। इस वर्ष राजस्थान से सर्वाधिक विद्यार्थियों का 100 एनटीए स्कोर बना है। जारी किए रिजल्ट में 44 स्टेट टॉपर्स की सूची भी जारी की गई है। इस बार जारी किए परिणामों में विद्यार्थियों को अपने एप्लीकेशन नम्बर एवं आवेदन के दौरान बनाए गए पासवर्ड से ही परिणाम प्राप्त होगा।

कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि जेईई–मेन जनवरी सेशन बीई–बीटेक के लिए 22 से 29 जनवरी के मध्य 5 दिन में 10 शिफ्टों में हुई थी। फाईनल आंसर–की 10 फरवरी को जारी की गई थी। जारी की गई प्रेस रिलीज के अनुसार परीक्षा के लिए 1311544 स्टूडेंट्स ने आवेदन किया था तथा 1258136 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। यह परीक्षा 13 भाषाओं में संपन्न हुई। देश के 304 परीक्षा शहरों के 618 परीक्षा केन्द्रों के साथ विदेशों के 15 शहरों में यह परीक्षा हुई। इस परीक्षा में 833325 छात्र एवं 424810 छात्राएं शामिल हुई। इसमें जनरल कैटेगरी के 466358, ईडब्ल्यूएस के 138699, ओबीसी के 490275, एससी के 122845 एवं एसटी के 39959 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। कैटेगरी वाइज भी 100 पर्सेन्टाइल वाले स्टूडेंट्स की सूची जारी की गई है।

> ■ **10 शिफ्टों में हुई परीक्षा में 14 स्टूडेंट्स ने 100 एनटीए स्कोर प्राप्त किया है, जिसमें राजस्थान के सर्वाधिक पांच विद्यार्थी, दिल्ली के दो, उत्तर प्रदेश के दो, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक एवं तेलंगाना का एक-एक विद्यार्थी शामिल हैं**

अमित आहूजा ने बताया कि जेईई–मेन जनवरी के परिणामों में 7 डेसीमल पर्सेन्टाइल के रूप में जारी किए गए। एनटीए स्कोर पर विद्यार्थियों में अपने–अपने पर्सेन्टाइल स्कोर के आधार मिलने वाले एनआईटीज, ट्रिपलआईटी एवं जीएफटीआई को लेकर उत्सुकता स्पष्ट दिखाई दे रही है।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 12 फरवरी, 2025

माघ मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा, बुधवार, विक्रम संवत 2081, आश्लेषा नक्षत्र सायं 7:35 तक, सौभाग्य योग प्रातः 8:07 तक, बव करण सायं 7:23 तक, चन्द्रमा आज सायं 7:35 से सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–मकर, चन्द्रमा–कर्क, मंगल–मिथुन, बुध–कुम्भ, गुरू–वृष, शुक्र–मीन, शनि–कुम्भ, राहु–मीन, केतु–कन्या राशि में।

कुमार योग रात 7:35 से सूर्योदय तक है। आज फाल्गुन संक्रांति, सूर्य कुम्भ में प्रवेश रात्रि 9:56 पर करेगी। पुण्य काल दिन 3:22 से आरम्भ होगा। आज सत्य पूर्णिमा व्रत, माघी पूर्णिमा है। आज माघ स्नान समाप्त होगा। आज होलिका रोपण, भैरव जयन्ती है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ–अमृत सूर्योदय से 9:55 तक, शुभ 11:18 से 12:41 तक, चर 3:27 से 4:50 तक, लाभ 4:50 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 7:10, सूर्यास्त 6:13

मेष
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

वृष
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

मिथुन
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आज परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

सिंह
घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा।

कन्या
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। आज शुभ–मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

तुला
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा।

वृश्चिक
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। आज शुभ–मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है।

धनु
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

मकर
परिवार में शुभ–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग–समन्वय बना रहेगा। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त–व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन
परिवार में शुभ–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।